अन्न भंडारों को बनाने के लिये विदेशी सलाहकारों से सहायता

1721. श्री ओम प्रकाश त्यागी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ,

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 35.75 लाख टन अन्न को रखने के लिए भण्डार बनाने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया है ,

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन भण्डारों का डिजाइन आदि तैयार करने तथा अन्य सलाह लेने के लिए विदेशी सलाहकारो की सहायता, बोर्ड की सम्पति के बिना ही, ली है और इस प्रकार से अपने देश के विशेषज्ञों की उपेक्षा की है और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने विश्व बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए है जिसके अधीन वह 35.75 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता का निर्माण करने हेतु सहायता प्रदान करेगा ।

(ख) बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकारों की भर्ती करने के लिए अनुमति दी है, अभी तक किसी भी सलाहकार की नियुक्ति नही हुई है । इस प्रयोजन के लिए केवल टेण्डर जारी किए गये हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खांडसारी उद्योगों में संकट

1722. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :
श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खांडसारी उद्योग को इस समय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड रहा है ,

(ख) क्या खाडसारी तथा चीनी के मूल्यो मे काफी कमी होने के कारण 50 प्रतिशत से अधिक खाडसारी कारखाने बन्द हो गये हैं और बहुत से बन्द होने की स्थिति मे हैं, और

(ग) क्या वर्तमान सकट का सामना करने तथा खाडसारी उद्योग को चलते रहने देने की दृष्टि से सरकार से आवश्यक सहायता तथा किस प्रकार की कर मे राहत की माग की गई है, और यदि हा, तो इस बारे मे सरकार ने क्या कदम उठाये है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) (क) खडसारी उद्योग से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमे यह आरोप लगाया गया है कि मूल्यों मे भारी गिरावट के कारण खडसारी यूनिटों को वित्तीय हानि उठानी पड रही है ।

(ख) राज्य सरकारों से विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) खण्डसारी पर लगे उत्पादन शुल्क मे 4-2-78 से पर्याप्त कमी कर दी गई है। मूल्यानुसार दर को 17-1/2 प्रतिशत मे घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और सल्फीटेशन प्लांटों की सहायता से कार्य कर रहे यूनिटों के बारे मे मिश्रित श्रेणी को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है

और ऐसे प्लांटों की सहायता के बिना कार्य कर रहे यूनिटों के बारे में यह 75 प्रतिशत तक कम कर दी गई है।

खण्डसारी उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए अन्य जो पग उठाया गया है वह यह है कि सभी खंडसारी व्यापारियों के लिए स्टाक सीमा को 1000 क्विटल से बढ़ा कर 5000 क्विटल कर दिया गया है।

खंडसारी के प्रति वाणिज्यिक बैंक पेशगी हेतु मार्जिन को निर्माताओं के बारे में 60 प्रतिशत से कम कर 35 प्रतिशत कर दिया गया है और अन्य के बारे में 75 प्रतिशत से कम कर 45 प्रतिशत कर दिया गया है ताकि खंडसारी की अधिकतम निकासी हो सके।

कृषि विस्तार प्रशिक्षण योजना के लिये विश्व बैंक से सहायता

1723. श्री चतुर्भुज : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा कृषि विस्तार प्रशिक्षण योजना के लिए राज्य-वार कितनी सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : भारत में कृषि विस्तार और अनुसंधान के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (जो कि विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था है) द्वारा प्रदान की जाने वाली राज्यवार सहायता की राशि निम्न प्रकार है —

राज्य	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण (दस लाख डालरों में)
1. उड़ीसा	200 0
2. मध्य प्रदेश	100.0
3. पश्चिम बंगाल	120.0
4. राजस्थान	130.0
5. असम	80.0
6. बिहार	80.0

Objective of Development of Rajasthan Canal

1724. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) what is the final objective of the development of the Rajasthan canal and how much time and money will be needed to achieve this objective, and

(b) how much time and money has already been spent on this project and what are the results achieved so far?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) and (b) The Rajasthan Canal aims to provide assured irrigation facilities to an area of 12.54 lac ha in the North-Western portion of Rajasthan to enable agricultural production in the desert area which otherwise is not possible

The estimated cost of the engineering works of the Rajasthan Canal is Rs. 404 crores of which an amount of Rs. 197 crores would have been spent by March, 1978, leaving a balance of